

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

बालचंद्र तनय ब्रजलाल अहिरवार ,

सिवा ग्वालियर
क्रमांक - 619-II-B

निवासी ग्राम बड़ाघाट तहसील वल्देबगढ़, जिला टीकमगढ़

.....आवेदक

वनाम

.....अनावेदक

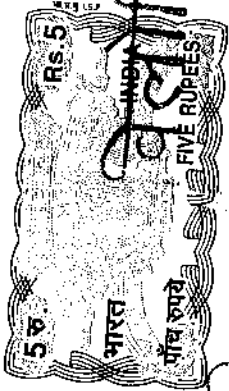
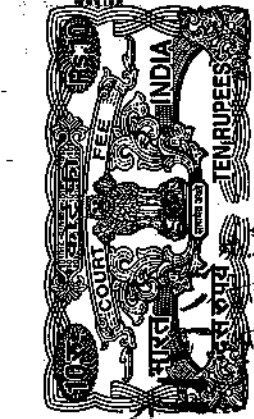
आवेदन/निगरानी अंतर्गत धारा ~~44/2~~⁵⁰ म० प्र० मू० रा० संहिता :-

आवेदक की ओर से निवेदन है:-

1- यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिका महोदय वल्देबगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र० क्र० 82/अपील/2008-09 में पारि आलोच्य आदेश दिनांक 25/03/2010 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के न से ग्राम बड़ाघाट स्थित भूमि खसरा नंबर 222/अ-19(4)/95-96 में पारित आ० क्र० 27/09/1996 के द्वारा बंटन किया गया था, आवेदक उपरोक्त भूमि पर लंबे समय काबिज हैं, उपरोक्त भूमि पर काफी धन एवं रूपा लगाकर उसे काफी उपजाऊ बना लिया है।

3- यह कि हल्का पटवारी बड़ाघाट द्वारा एक प्रतिवेदन तहसीलदार वल्देबगढ़ को प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के नाम प्रविष्टि फर्जी अतः उसे निरस्त किया जावे। जिसको तहसीलदार द्वारा 115-116 के तहत सुनवाई लेकर अपने द्वारा प्र० क्र० 32/अ-6अ/08-09 दर्ज करके अपने द्वारा पारित आ० क्र० 26/06/2009 के द्वारा आदेश पारित करके वादग्रस्त भूमि म० प्र० शासन के नाम करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिक महोदय वल्देबगढ़ जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वारा



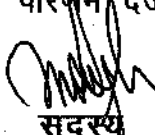
सिवा ग्वालियर
क्रमांक - 619-II-B
19-2-16

१९

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 619-J/16 जिला झारखण्ड

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	<p>1- मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता ने यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वल्लेवगढ़, द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 25/03/2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक के अनुसार उसके नाम से ग्राम बड़ाघाट में भूमि खसरा नंबर 36/4/10/1 अ में से रकवा 1.214 हैक्टर का बंटन किया गया था, जिस पर आवेदक लंबे समय से काबिज है। हल्का पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण 115-116 के तहत पंजीवद्ध करके वाद भूमि पर से आवेदक का नाम पृथक करने का आदेश पारित कर दिया। अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि भूमि को उपजाऊ बना लिया है, प्रकरण क्रमांक 222/अ-19/95-96 में पारित आदेश दिनांक 27/09/1996 के द्वारा बंटन किया गया था।</p> <p>3- प्रकरण में तहसीलदार द्वारा 13 साल बाद प्रकरण दर्ज करके पारित आदेश दिनांक 26/06/2009 के द्वारा संहिता की धारा 115-116 के तहत कार्यवाही की है, जबकि उन्हें एक साल की प्रविष्टि सुधारने का अधिकार है। आवेदक की ओर से 2011 रानि 273, कमला सिंह वनाम शासन का न्याय दृष्टांत भी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों से सहमत होकर निगरानी स्वीकार की जाती है, दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण की वाद भूमि पर आवेदक का नाम पूर्ववत दर्ज हो, प्रकरण का परिणाम दर्ज कर संचित अभिलेख हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	

